

जिंदगी बदलने वाले प्रेरक विचारों को अपने जीवन में हमेशा अपनाए।
- अज्ञात



बातचीत अंतिम दौर में है

द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था के सहारे अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उड़ानें शुरू होने की बाकायदा घोषणा हो चुकी है, जबकि अन्य कई देशों के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। इससे पहले बबल व्यवस्था के ही तहत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का एक मैच संपन्न हो चुका है।

ललित नेगी।

धन्य कहें एयर बबल को, जिसकी बदौलत पिछले चार महीने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक अब हटने लगी है। द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था के सहारे अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उड़ानें शुरू होने की बाकायदा घोषणा हो चुकी है, जबकि अन्य कई देशों के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। इससे पहले बबल व्यवस्था के ही तहत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का एक मैच संपन्न हो चुका है। कोरोना कालीन पाबंदियों के दौर में बबल उम्मीद की किरण दिखाने वाला शब्द बनता जा रहा है।

यह कोरोना से पहले का नॉर्मल दौर तो नहीं, लेकिन नॉर्मल से एक कदम पहले वाली स्थिति बहाल करने का जरिया

जरूर बन रहा है। हालांकि हवाई यात्राओं और क्रिकेट मैच के संदर्भ में उपयोग किए जा रहे इस एक शब्द के अर्थ काफी अलग-अलग हैं। क्रिकेट में इसका मतलब है, दो देशों के खिलाड़ियों और मैच में भूमिका निभाने वाले चुनिंदा लोगों के लिए एक ऐसा बबल बनाना जिसमें वे टीवी कैमरों के जरिये सबको दिखें लेकिन कोई भी बबल के अंदर जाकर उनसे मिल न सके।

मतलब यह कि खिलाड़ियों और तमाम सपोर्ट स्टाफ सहित ये सारे लोग जिस होटल में ठहरेंगे वहां से लेकर स्टेडियम तक बाहर का कोई भी इंसान इनके पास नहीं जाएगा और न ही ये किसी से मिलेंगे। इस बीच ये सैनटाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगे और इनके नियमित कोरोना परीक्षण होते रहेंगे। पिछले दिनों इसी

बबल को तोड़कर थोड़ी देर के लिए घर चले जाने के चलते इंग्लैंड के बोलर जोफ्रा आर्चर न केवल बैन हो गए बल्कि हर तरफ से उनकी लानत-मलामत भी हुई।

हवाई उड़ानों के संदर्भ में बबल शब्द का मतलब थोड़ा अलग है। इसमें ऐसा कोई घेरा बनाने की बात नहीं है, लेकिन कठोर पाबंदियां यहां भी हैं। इसके तहत शुरू हो रही उड़ानों में ओपन बुकिंग के तहत किसी को भी टिकट बुक कराने की सहूलियत फिलहाल नहीं होगी। विभिन्न देशों की अपनी शर्तें हैं। ज्यादातर मामलों में वही लोग यात्रा कर पाएंगे जिनके पारिवारिक सदस्य (पति या पत्नी) गंतव्य देश के स्थायी निवासी नागरिक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। हर यात्री को कोरोना टेस्ट के नेगेटिव रिजल्ट वाला सर्टिफिकेट

साथ रखना होगा और उन पर क्वारंटीन संबंधी पाबंदियां भी उस जगह की लागू होंगी जहां वे लैंड करेंगे।

साफ है कि यह फ्री मूवमेंट जैसी स्थिति नहीं है। न तो क्रिकेट खिलाड़ी कोरोना से पहले के सुनहरे दिनों वाला थ्रिल महसूस कर सकते हैं, न ही एक से दूसरे देश को जा रहे लोग। आज के हालात में यह संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। फिर भी 'बबल' के अंदर अधिकतम सुरक्षा के साथ कारोबार शुरू हो रहा है। खेल आखिर हो रहा है, उड़ानें शुरू हो गई हैं। प्रयोग सफल रहा तो इसी बबल व्यवस्था को बॉलिवुड, टीवी सीरियल, मॉल, होटल इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में भी लागू करते हुए हम धीरे-धीरे हालात को एक हद तक कामकाजी बनाने की ओर बढ़ेंगे।

बर्दाश्त

अशोक वोहरा। अगर आप समस्या को स्वीकार करते हैं और उस सर्वशक्तिमान से इसे बर्दाश्त करने की ताकत मांगते हैं तो शायद आप ज्यादा नुकसान के बिना इस संकट से उबर सकते हैं। स्वामी जी बोलें "क्योंकि आप मुझसे भी बड़े संन्यासी हैं..." "मैंने तो ईश्वर के लिए इस संसार का त्याग किया है... परंतु आपने तो इस संसार के लिए ईश्वर को ही त्याग दिया है..." जब त्याग के लिए बाध्य किया जाता है.. तो यह बहुत कष्टप्रद है.. परंतु जब कोई आस्था के वशीभूत होकर ऐसा करता है तो यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देता है। हमें एक कार खरीदने की इच्छा हो सकती है हमें एक मकान खरीदने की इच्छा हो सकती है हमें इतिहास या विज्ञान का अध्ययन करने की इच्छा हो सकती है या हमें इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा हो सकती है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

अस्मिता का मोदी प्रयोग

दिलचस्प बात है कि आज जिस क्षेत्रीयता के मुद्दे पर क्षेत्रीय दल मोदी फैक्टर को काउंटर करना चाहते हैं, उस राजनीति में कभी प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर गुजरात सीएम महारत हासिल कर रखी थी। गुजरात में उन्होंने राज्य की अस्मिता का मुद्दा उठाकर बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की थी। उन्होंने खुद के काम को 2007 के विधानसभा चुनाव में गुजराती अस्मिता से जोड़ते हुए पहली बार इस दांव का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था।

जानकारों के अनुसार ऐसे मुद्दे हमेशा राष्ट्रीय दलों को परेशान करने वाले होते हैं। जिस दल की सरकार केंद्र में रहती है, उसे भी ऐसे मुद्दे मुश्किल में डालते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों को इसमें भावना भड़काकर वोट लेने में आसानी होती है। कोई भी राष्ट्रीय दल किसी क्षेत्रीय मुद्दे पर साफ स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि इसके असर बहुआयामी होते हैं। वहीं क्षेत्रीय दल के लिए यह अवसर की तरह होता है। चूंकि देश में क्षेत्रीय दल अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए वे क्षेत्रीयता का दांव चलकर वोट बटोरने का रास्ता अपना सकते हैं। कभी हिंदी थोपने के नाम पर, तो कभी संसाधनों में हक को लेकर दक्षिण के राज्य बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे देश में राष्ट्रवाद, आक्रामक हिंदूवाद जैसे मुद्दे को स्थानीय स्तर तक स्थापित करने में सफल रही है। इसका लाभ पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिल भी रहा है। ममता बनर्जी की बीजेपी के इस कार्ड को क्षेत्रीयता जैसे मुद्दे से काउंटर करने की रणनीति कहां तक सफल होगी, वह अगले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है।

इस बार ममता बनर्जी की यह वर्चुअल रैली अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत मानी जा रही है।

सफल सियासी ट्रेंड

नरेंद्र नाथ

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ममता बनर्जी ने वहां क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड खेलने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस के मौके पर यह दांव खेला। बीजेपी को राज्य के लिए बाहरी पार्टी करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य को बंगाल के ही लोग चलाएंगे, न कि कोई बाहरी लोग। दरअसल हर साल 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती हैं, क्योंकि उसी दिन पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई थी। इस बार ममता बनर्जी की यह वर्चुअल रैली अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। ममता के करीबियों के अनुसार आगे इस अभियान को वह क्षेत्रीय अस्मिता से और भी अधिक जोड़ेंगी। दरअसल दस सालों के शासन के बाद ममता बनर्जी को पता है कि इस बार एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है और खतरा मुख्य रूप से बीजेपी से ही है।

बीजेपी ने वहां हाल के सालों में अपने संगठन को मजबूत बनाने में सफलता भी पाई है। 2019 आम चुनाव में राज्य की 42 सीटों में बीजेपी को 19 सीटें मिली थीं। तभी से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।



लेकिन यह भी सही था कि आम चुनाव में बीजेपी की सफलता के पीछे मोदी फैक्टर और अमित शाह का मैनेजमेंट का बड़ा योगदान था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया कि वह इस चुनाव को स्थानीय चुनाव का रूप देते हुए खुद को बंगाल की बेटे के रूप में पेश कर सकती हैं। अब तक राज्य में उनके सामने बीजेपी का कोई स्थापित चेहरा या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। अभी तक का संकेत भी यही है कि बीजेपी राज्य में बिना किसी चेहरे के उतर रही है। उसी का लाभ उठाने के लिए ममता बनर्जी ने अभी से क्षेत्रीय कार्ड सामने रख दिया है। दरअसल ममता को पता है कि नरेंद्र मोदी की

लोकप्रियता में अभी कमी नहीं आई है और अगर वह ममता बनाम मोदी को चुनाव में सामने रखती हैं, तो नुकसान उनका ही होगा। इस बार ममता बनर्जी के चुनाव के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं और वे बिहार में नीतीश कुमार से लेकर हाल ही में केजरीवाल तक क्षेत्रीय अस्मिता के इस रूप का फायदा सफलतापूर्वक उठा चुके हैं।

दरअसल हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती झेल रहे क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय क्षेत्र पर हर जगह क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। चाहे वह कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, तमिलनाडु-ओडिशा हो या आंध्र प्रदेश, सभी जगह क्षेत्रीय अस्मिता राजनीति पर हावी है। राष्ट्रीय स्तर पर अजेय दिख रहे बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों का ऐसे मुद्दे पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कहीं अलग राज्य को लेकर, तो कहीं स्थानीय लोगों को वहां के संसाधनों पर अधिक हक दिए जाने के नाम पर मुद्दे उठते रहे हैं।

दक्षिण भारत में तो कई दशकों से क्षेत्रीयता के मुद्दे सियासी धारा तय करते रहे हैं। कुछ साल पहले तो दक्षिण के राज्यों ने केंद्र की ओर से जारी होने वाले फंड में अपने हिस्से को लेकर एक फ्रंट बना दिया था, जिससे केंद्र सरकार भी बड़ी चिंता में पड़ गई थी।

अष्टयोग-5121

6	7		5	
2	28	40	7	35
		5	6	4
5	28	38	34	1
4	2			1
	31	2	24	1
7	1	4		5

प्रस्तुत खेल सुबोक् व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, गहरे काले रंग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगा, चौथी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक हीना अनिवार्य हैं।

अपना ब्लॉग

चेहरे के नाम पर यह कार्ड

मोहन। क्षेत्रीय अस्मिता के कई रूप भी रहे हैं। कहीं चेहरे के नाम पर यह कार्ड खेला गया तो कहीं क्षेत्र के नाम पर। कहीं-कहीं प्रांत को खास दर्जा देने की मांग भी हाल के सालों में अहम मुद्दा बनी रही है। इसने भी क्षेत्रीयता की जंग को बढ़ाने का काम किया है। बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य पिछड़ेपन या वक्त की जरूरत बताकर अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते रहे हैं। इस मांग का आशय उस राज्य को मिलने वाले बजट से होता है, लेकिन हकीकत में देखें, तो यह मुद्दा भी क्षेत्रीयता की जंग में तब्दील होता जा रहा है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की ओर से बिहार स्वाभिमान का मुद्दा उठाया गया था। जब देश की हिंदी बेल्ट में भी क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ा, तो इस तरह के मुद्दे इस इलाके में भी उठने लगे।

